

GENERAL STUDIES (Test-10)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/23 (J-A)-M-GSM (M-III)-2310

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Praduman kumar Mobile Number: _____
Medium (English/Hindi): Hindi Reg. Number: _____
Center & Date: JVeharurihar 29/08/23 UPSC Roll No. (If allotted): 0811492

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.	4	11.	6
2.	4	12.	5
3.	4.5	13.	7
4.	3.5	14.	5
5.	2.5	15.	4.5
6.	4	16.	5.5
7.	3.5	17.	5
8.	3.5	18.	4.5
9.	3.5	19.	5
10.	2.5	20.	5.5
Grand Total (सकल योग)		88.5	

FL 211

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)

Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)

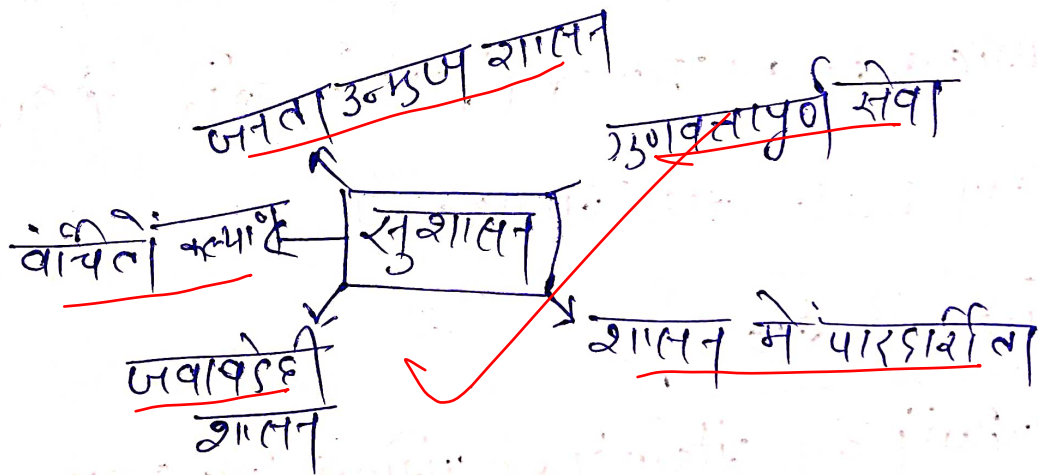
Reviewer (Signature)

1.

सुशासन की अवधारणा की चर्चा कीजिये और ज़मीनी स्तर पर सुशासन की संवृद्धि में 'ई-ग्राम स्वराज' की क्षमता को रेखांकित कीजिये। (150 शब्द) 10
 Discuss the concept of good governance and highlight the potential of eGramSwaraj in enhancing good governance at the grassroots. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सुशासन से तात्पर्य शासन की द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की जनता तक उत्प्रेत पहुँच है। संविधान के अनुच्छेद (38) में सुशासन से संबंधित प्रावधान है।



सुशासन को बढ़ावा देने हेतु ई-ग्राम स्वराज परियोजना की उद्देश्य है -

- ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का निष्पक्ष प्रिया-व्ययन होगा।
- शासन, सुशासन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी।

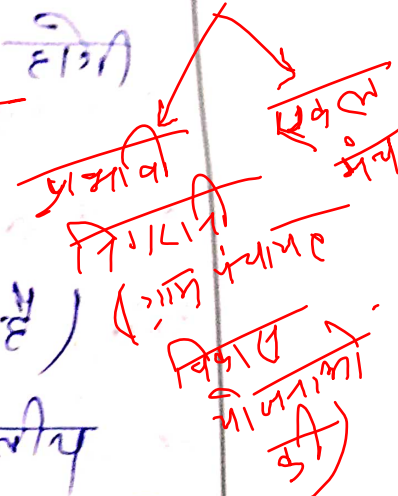
* प्रौद्योगिकी इंटरनेट नी त्रिपान्वयन में माइक्रो आधेगी ।

→ पंचायतों का डिजिटलीकरण

* सेवा तक उचित एवं तीव्र पहुंच होगी

चुनौतियाँ

- शिक्षा का अभाव है (74% लाइवलाइंडर है)
- डिजिटल डिवाइड है (WRU → 54% भारतीय इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं कले)
- जागरूकता का अभाव (शा.के.बारे में भी गहन 33% लोग जागरूक हैं)



आगे की राह

- ग्रामीणों का प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण दिना जागरूकता
- डिजिटल डिवाइड को कम करना (डिजिटल भारत मिशन)
- माइक्रो एंटरप्राइज (100% नामांकित काराएँ)

A/10

सुशासन के लिए ई-ग्राव द्वारा पहल के निष्पक्ष त्रिपान्वयन द्वारा उपेक्षित चुनौतियाँ के निराकरण की आवश्यकता है

2.

भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र के कम उपयोग पर विचार कीजिये और उनके उपयोग में सुधार के उपाय प्रस्तावित कीजिये। ADR के अंगीकरण में व्याप्त बाधाओं को दूर करने में ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) की क्षमता का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हार्शिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

Discuss the underutilization of ADR mechanisms in India and propose measures to improve their usage. Evaluate the potential of Online Dispute Resolution (ODR) in overcoming barriers to ADR adoption. (150 words) 10

परम्परागत न्यायिक प्रणाली से बहार
विवादों का समाधान करने की प्रक्रिया को
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कहते हैं

कम उपयोग

- परम्परागत प्रणाली प्राचीन कालिके का अह
- कैसल का बाध्यकारी न होना
- तीसरा उपक्ष बीच में ही विवाद समाधान ले हल सकता है
- स्पष्ट विशा निर्देश का अभाव
- जागरूकता का अभाव

↳ ADR मुख्यतः
T.I. शहरों में
की बेजिस्ट है।

सुधार

- प्रतिनिधियों को बाध्यकारी करना चाहिए।
- स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी प्रयोग से निष्पत्ता लंबे काये।

→ लैबन में
रूपरेखा
सूखे।
→ वाणिज्यिक मामलों
में महयक्षता को
आमिनाय
किया जा
सकता है।

→ जनता वन और इन्फ्रान्ज डिपा जाये

→ ना लिखें
(Candidate must not write on this margin)

आमलादन विवाव समाधान

→ क्या है?

→ समय कम लगता है (तीस मिनट)

→ लागत खर्च 90% तक कम हो जाता है

→ प्रौद्योगिकी उपयोग से कितना होला है पादकारीता बढ़ती है

→ दुर्गम हिलो, पहाडी हिलो तक पहुँच आसानी

→ आरूपक
डेटा
प्रमाण
से
बचें

अधे बीराए

→ नजों की संख्या बढ़ाई जाये वर्तमान में प्रति 10 लाख पर 15 नज है।

→ डिजिटल जागतकता बढ़ाई जाये (डिजिटल भारत मिशन)

→ जनता को जागतक डिपा जाये।

अध्यापिक त्रगावी के आतेहिल्ल
आर डो कम करने की डिवा मे ODR,
ADR महत्वपूर्ण व्यापिक लेना सकते हैं

→ 5 करोड़
केल
लंकिट
है

4/10

3. मणिपुर पर अधिरोपित अनुच्छेद 355 से संबंधित हालिया चर्चाओं के आलोक में राज्यों की सुरक्षा के लिये संरक्षक के रूप में केंद्र सरकार की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

(150 शब्द) 10

In light of the recent discussion on imposition of article 355 on Manipur, critically analyze the role of the Union government as a guardian for protecting the states. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not)

write on this margin

राज्यों की आन्वयिक एवं बाह्य खतरों से सुरक्षा काला अनुच्छेद 355 के बदल काला कारण है।

हाल ही में मणिपुर इस दिल के लिए उल्लेख है अनुच्छेद 355 क्रिया-व्यपन डिया गया है।

केंद्र सरकार की भूमिका

- केंद्र सरकार बाह्य खतरों से राज्य की सुरक्षा काला है।
- आंतरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा शांति बचाये रखना केंद्र कार्य है।
- संवैधानिक बन्ध के विकल्प होने पर (अनुच्छेद 355) राज्यपाल शासन लागू काला है।
- केंद्र द्वारा शांति एवं सुरक्षा होने निर्दिष्ट डिया जाना है।

नकारात्मक प्रभाव

→ कई अस्पष्ट शब्द
इ जैसे - आंगिक अशांति

उम्मीदवार को इस
प्रश्न में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must
write on this margin)

→ कभी - राजनैतिक दित के लिए राष्ट्रपति

शासन लागू करना (इंदिरा गाँधी कार्यकाल)

दौरान 49 बार राष्ट्रपति शासन लगा।

→ केंद्र - राज्य विवाद, कहते हैं विवाद
में कभी झगती हैं।

→ सहकारी मधवों की भावना को विनष्ट

→ राज्यों के उच्चतम विकास के
विनष्ट हैं।

→ केंद्र राज्य संबंधों को मधुर

रखाये रखना एवं राज्य की सुरक्षा का

केंद्र का कर्तव्य है वह द्वारा में युद्धी

आयोग एवं सकारिता आयोग की

सिफारिशों को मानना चाहिए।

4.5
10

4. न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का एकीकरण न्याय तक पहुँच में दक्षता और प्रसदर्शिता को कैसे बढ़ावा दे सकता है? डिजिटल न्यायिक पहल के सुचारु कार्यान्वयन में कौन-सी बाधाएँ मौजूद हैं? उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

How can the integration of technology in the judiciary promote efficiency and transparency in access to justice? What are the obstacles to the smooth implementation of digital judicial initiatives? Suggest measures to overcome them. (150 words) 10

स्वपनीय लिपि वगैरह नाम भारत संघ का मे लुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि न्याय तक पहुँचें कराना, 18-21 के तहत मूल अधिकार है।

- न्यायपालिका पालिका
- डिजिटल कोर्टलय
 - अनलार्डन विचार समाधान
 - आइलार्डन शिक्षापर समाधान
 - ग्राहक-केंद्रित सलाह कालक्रम

बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का न्यायिक कार्यवाही का लीखा प्रमाण होता है।

महत्व → Heading का प्रयोग प्रश्नानुकूल करें

- न्याय तक नज़ी पहुँच होनी है
- न्यायिक प्रणाली की क्षमता बढ़नी है → कैसे?

प्रश्न में यही पूछा है

उम्मीदवार को परीक्षा में उनी लिखनी चाहिए।
(Candidate must write on this margin)

- लगात प्रभावी होना है (90% कम)
- लगात हाल कम होना है

बाधाएं

कारकाश्रीता कैसे आसिगी?

- पहाडी दुर्गम होना व बुरा लावा नही है
- डिजिटल विभाजन (युवा लोगे बलवान बन गये करते)
- क्षेत्रीय असमानता (महाराष्ट्र में ज्यादा) विद्या में कम इंटरनेट उपलब्धता है
- शिक्षा का निम्न स्तर है उपलब्धतापूर्ण शिक्षा का अभाव → डैला सुरक्षा

उपाय

3.5 / 10

- ई-कॉर्ट से N-कॉर्ट को खोला जाना
- प्रौद्योगिकी तक पहुँच बढ़ाना
- शिक्षा स्तर सुधारना
- आवर्तित विद्या का ^{समाधान} बढ़ावा देना

न्यायपालिका की दृष्टि की
बढ़ाने एवं आए को कम करने हट्टे
प्रौद्योगिकी प्रभावी भूमिका आता कर सकनी है

5. भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यों की चर्चा कीजिये। ED के दुरुपयोग से जुड़े मुद्दों की भी चर्चा कीजिये और इसे रोकने के उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10
 Discuss the functions of the Enforcement Directorate (ED) in India. Also, touch upon the issues surrounding misuse of ED and suggest ways to curb it. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस दृष्टिकोण में नहीं लिखना चाहिए।
 (Candidate must not write on this margin)

अर्थ धन, बैनामी संपत्ति संबंधी मामलों के निराकरण के लिये प्रवर्तन निदेशालय का गठन किया गया है यह साक्ष्य अपराध, मनी लाँड्रिंग जैसे मामलों की जांच करता है।

↳ आर्थिक सुफ़िया एजेंसी

↳ ED के कार्य क्लॉस - PMLA, FEMA, FEOA

मुद्दे

→ NCRB के डेटा के अनुसार ED द्वारा जांच की जाने वाली कार्रवाइयों में 60% ही सही होते हैं

→ कड़े ढाल राज्य को डराने के रूप में प्रयोग किया जाता है

→ राज्य के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप

→ कड़े राज्य संबंध प्रभावित, संबंधकारी महत्वा के विरुद्ध है

→ निर्णय के लक्ष्यता की डर बहुत कम है

उपाय

→ ED के क्रिया-व्ययन के संबंध में सूक्त
दिशा-निर्देश

→ केंद्र - राज्य सहायता एवं विभागीय
सहायता को बढावा देना

→ राज्य के विरुद्ध सत्त्वनायक हो

→ निरपेक्ष कार्यवाही एवं पारदर्शिता
संचालन हो।

2.5
10

मांसक
उत्तर
दो

अर्थ वचन आतिजैकी
समस्या को समाप्त करने हले (ED) मुख्य
व्यक्ति-निर्देशात्मक है अतः मुद्दों का समाधान
का ED की प्रभावशीलता को बढाने
की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखने
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

6.

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका केंवल सीमांत रही है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

In the realm of women empowerment, the role of civil society and NGOs has been only marginal. Critically examine this statement. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हार्शिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

महिला कार जैसे परिवेदा का निर्माण
करना जहाँ महिला अपने जीवन से संबंधित
निर्णय पूर्व आत्म विश्वास को सापु ली सबे
महिला सशक्तीकरण कहलाता है।

नागरिक समाज की भूमिका

- * महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया है (राजस्थान
के आजीवक स्वयं सहायता समूह)
- * गरीबी से बाहर निकालना है (कैलस का
वैल्युथमी लगाने)
- * जागतिक क। शिक्षण कला है (दिल्ली
का जन NGO)
- * महिला अधिकारों के प्रति समर्पित
NGO की है।
- * गौन शोषण को उजागर कर माप
दिलाने में ही कमल रहता है

34/6/20

* स्वावलंब साधिकाओं तक पहुँच बढ़ाना देना है।

→ कौशल व सतत शिक्षण का वैकल्पिक स्रोत

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

सीमांत ग्रामीणों के कारण

- नागरिक संगठनों के प्रावधान का अभाव
- वित्त का अभाव रहता है।
- शारीर क्षेत्रों में रूप लक्ष्य रहते हैं।
- स्थानीय, शारीर जनता को जानकारी नहीं है।
- पर्याप्त लक्ष्यी योजनाएँ न दिए जाना
- निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी

उपाय

4/10

- जागरूकता
- वित्त उपलब्ध करना
- निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना
- लक्ष्यी योजनाओं तक पहुँच बढ़ाना
- महिला सशक्तिकरण के लिए
- NGO की उपयुक्त सहायता को हल करना
- आनीवार्य है

7. भारतीय संविधान में राजकोषीय संघवाद का संतुलन केंद्र के पक्ष में क्यों अधिक झुका हुआ है? राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति के लिये यह कहाँ तक जिम्मेदार है? इसमें सुधार के उपाय सुझाइये।

(150 शब्द) 10

Why is the balance of fiscal federalism in the Constitution tilted in favour of the centre? How far is this responsible for the poor financial health of states? Suggest measures to improve it. (150 words) 10

राजकोषीय संघवाद की बात करें (268-293 अनुच्छेद)

संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं साथ ही सातवीं अनुसूची में शामिल विषय क्षेत्र की ओर अधिक है।

केंद्र के पक्ष में क्यों है

- केंद्र पर अतिरिक्त भार है (बाह्य आक्रमण से रक्षा)
- विदेश नीति संघ में केंद्र अधिक है (द्विपक्षीय को 3 विकल्प और दिए हैं)
- अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान दिया जाता है
- किसी नए कल्याणकारी योजना चलानी होती है (मरगा, PM समान नीति)
- देश के विकास हेतु RESD का स्वयं को बनाना (वर्तमान में 0.4% है)

उम्मीदवार क हारिये में न चाहिये। (Candidate n write on this

राज्य की खराब लिये लि लिये जिम्मेदार

सलीमता मात्रा में जिम्मेदार है (कम विषय

इ रले)

→ राज्यों की खराब प्रणाली जिम्मेदार है

→ शुल्कान्यास, पाइपराय की कमी लक्ष्या है

→ पर्याप्त उधमशीलता को बहाल न लेना

→ लोक सुभावन योजना में अधिक धन (MP हाल किलमों का बर्ष माफ)

4 सखीप्रान्तक
कारण
↓
उपकर परिसर
और
आविष्कार

प्री की ल
कल्प

↳ कर राबइव में जिउमद

उपाय

→ बिना आयोग का डी जने वाली शाही बहाली जा लकली है

→ बाजार लिये कर्म लेने की अडमालि डेना

→ राज्य की समलव प्रणाली को डुक्ल करना

→ राज्यों के दिलों को बहाल देना।

देश के समावेसी विकास

के लिये राज्य लवं कने डानों लकली है

3.5
10

8. भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की त्रिपक्षीय पहल के महत्त्व को उल्लिखित कीजिये। विश्व राजनीति में भारत की स्थिति को मजबूत करने में भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय समझौतों की क्या भूमिका रही है? (150 शब्द) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

Bring out the significance of the trilateral initiative of India, UAE, and France. What is the role of bilateral deals by India to UAE and France in solidifying India's position in world politics? (150 words) 10

भारत अपनी पश्चिम की ओर देशी नीति को बढ़ावा देते हुए आग्नी देवा, यूरोप के साथ संबंध बना रहा जैसे 12V2 पहल आदि।
रूसी दिशा में फ्रांस, UAE, दक्षिण पहल महत्वपूर्ण है।

महत्त्व.

- भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी (UAE से 70% तेल आपात होता है)
- द्विपक्षीय देवा से आग्नी देवा से बाकि को प्रतिकूल का वा
- फ्रांस साथ पिछका खरद सौभाग्य का सिक्का
- भारत अपना निर्पत बना सकता है (UAE के साथ भारत का व्यापार सुदृढ़ है)

→ लक्षा लक्षा = राफेल

→ खादी डेवों तक पड़च्ये स्थितिये होली है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत की मजबूत स्थिति में युद्ध

→ विभिन्न मामलों में भारत का समर्थन करना (खास 370 हलाने का समर्थन)

→ UNSC में स्थायी वीट की हकदारी का समर्थन करना

→ भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में यूएफए

भारत की जलवायु तालिका संरचना होने की जरूरी है (सौर ऊर्जा संरचना)

क्रॉस एवं UNF दोनों भारत की विवेक नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारत के आगापी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग देना की सम्भावना है।

UNF का
संबंध
अलग
वर्क

3.5
10

9.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की कार्यप्रणाली 'संस्थागत आकांक्षाओं' और 'शासी राजनीति' के बीच गहरी असंगति को दर्शाती है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

(150 शब्द) 10

The functioning of CBI and CVC reflects "a deep mismatch between institutional aspirations" and "governing politics." Critically Analyze.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

शुल्काचार पर धनी के संस्थानय साधित
की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग
1964 एवं CBI का गठन दिया गया। 2003
सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा
दिया गया। CBI केंद्रीय विरोध दिल्ली
पालिसी Act 1948 से शासित कार्य करती है।

संस्थागत आकांक्षाएँ

- शुल्काचार पर रोड लगाना
- पारदर्शिता लाकर शासन में
- जनता व शासन बीच की दूरी कम करना
- शुल्क अफसरों को जाली कार्यवाही करना
- देश को में उन्नततरी उर्ध्व मार्ग ल बनाना

शासी राजनीति

- केंद्र की अधीन कार्य करती है

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

- 30 ने CBI को पिदरे का लोवा कहा है
- राज्यों के कितने प्रयोग होला है।
- राजनीतिक हित को बहाल दिया जाना है।
- राजनीतिक प्रभाव अधिक रहता है।

रुक ही
बिन्दु

गहरी असंगति

- संसदीय एवं राजनीतिक हित साथ में
बही लय सकते
- श्रद्धाचार को राजनीति हस्तक्षेप के बिना
ही पिताया जा सकता है।
- दोनों ही कार्य बेहतर रूप से नही हो
पाते

राज्यों द्वारा सामान्य
सम्पत्ति कापल
लेना

- उपाय → राजनीतिक निष्पक्षता बनाना-चाहिए।
- सरकारी आयोग की सिफारिश
- राज्य के मामलों में अनावश्यक
हस्तक्षेप नही

3.5
10

CVC, CBI जैसे की श्रद्धाचार शुद्ध बनाना एवं शासन की वादविस्तारिता बनाने हेतु मुख्य एजेंसी है। इन्हें राजनीतिक प्रभाव को कम करना चाहिए।

10.

पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण करते हुए भारत की पेंशन प्रणाली की अपर्याप्तता की चर्चा कीजिये। सभी नागरिकों के लिये समतामूलक और सुदृढ़ पेंशन प्रावधान सुनिश्चित करने के लिये व्यापक सुधारों का प्रस्ताव कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the inadequacy of India's pension system, analyzing issues with Old Pension Scheme (OPS) and New Pension Scheme (NPS). Propose comprehensive reforms to ensure equitable and robust pension provisions for all citizens. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
कॉपी में नहीं लिख
ना है।
(Candidate must
write on this margi

मूनिका
के
OPS,
NPS
की
समस्याएँ

2004 में के. एल. गांधी द्वारा नई पेंशन प्रणाली की शुरुआत की गई जिसमें सेवा निवृत्तों के लिए आयुश्रम पेंशन या रोड गारंटी रक्षा हितों में अन्तर्गामी पुरानी प्रणाली कायम है।

- मुद्दे - पुरानी पेंशन प्रणाली प्रागे बना
- बायनीलिब्रि लागू होने से लोगों द्वारा लाइ डिजायना (खारजण)
 - सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्थिति खराब हो
 - पेंशन का बायनीलिब्रि से प्रभाव होगा

repeat

पेंशन प्रणाली की अपर्याप्तता

- सरकार पाल बिजली की कमी
- वैकल्पिक समाधान तंत्र (गौरी दौलत का कलवा)
- कर्मचारियों की वही लंबा
- केन्द्र - राज्य सहायता का दबाव

सुधा

- * बीमा जैसी योजनाओं स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुंच बढाना (वर्तमान में 20-10 है NFHS)
- * केन्द्र राज्य सहयोग द्वारा एकीकृत पैरान प्रणाली लागू करना
- * पैरान प्रणाली को राजनीति से दूर रखना
- * कर्मचारियों के लेवानीप्रति डे का स्वास्थ्य समस्या को लिये राज्य प्रतिबद्ध हो
- * वैद्यों तक पहुंच प्रदान का मंथली पैरान बढाना (वयं बढना योजना)

2.5
10

1/15/20
2/20

सरकारी कर्मचारी सरकार ही जिम्मेदारी होते हैं कतः लेवानीप्रति डे का उन्हे दिली या विचार डिया जाना चाहिए। तथा नये पैरान प्रणाली में उन्हे अनुकूल सुधा डिये जाय।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

11.

हमारी संसद की संवैधानिक भूमिका विचार-विमर्श करना और विधि का निर्माण करना है। हालाँकि, संसद के कामकाज में लगातार गिरावट आ रही है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15
The constitutional role of our Parliament is to deliberate and enact laws. However, there has been a steady deterioration in the functioning of Parliament. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को हाशिये में नहं चाहिये। (Candidate r write on this

संविधान के अद्वैत 74 के तहत संसद संबंध में प्रावधान है। जिसके तहत संसद का जड़न लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से फिल्टर होगा। संसद का कार्य विधि का निर्माण करना है देखा के लिये नालन संचालन को देखा देना है।

संसद की भूमिका

- विधायी भूमिका
- कार्यकारी भूमिका
- विवेकीय/न्यायिक भूमिका

- देखा को सामाजिक कार्य, राष्ट्रपति के सहायता के केन्द्रीय संस्थाएँ
- सरकार संचालन हेतु विधि का निर्माण करती है।
- संविधान संशोधन माध्यम से संविधान को प्रसंगिक बनायी रखती है।
- नये-नये विचारों, विचारधाराओं को कपनात्मक है। (1981 में पुर्नजीवा को अयनाना नवर आर्थिक नीति) 23

→ विदेश नीति की लक्ष्य द्वारा लक्ष्यित
होती है।

→ बजट प्राथम्यता द्वारा इसे का आधार
लक्ष्य निर्धारित होता है।

हाल ही में लक्ष्य
की उत्पादकता में कमी आई है वर्तमान
में लोकसभा की उत्पादकता 72% रही
राजसभा की उत्पादकता 77% है।

उत्पादकता कमी के कारण

→ विपक्ष द्वारा आधार विरोध किया जाना

→ लक्ष्य द्वारा की विपक्ष के प्रति
असंतोषशील रवैया

→ सापेक्षिकी कम प्राप्त होना (16वीं
लोकसभा में 27% रिपे 27वीं 17% रिपे)

→ किसी विषय विपक्षी कड़े कानून
पास कराने द्वारा 370, कृषि कानून)

उम्मीदवार को इस
दरिचय में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

अल्पाधिक अवकाश पर की लम्बा है

झागे की राह

एक विधेयक का उद्देश्य
अध्यादेश का उद्देश्य

→ संसद के दिनों की लम्बा पहाकर 120
करना चाही।

→ विपक्ष द्वारा वेल्ड विकल्प लक्ष्य लुप्त
देना

→ लापितियों को मातृ शक्ति का
संतीप

→ लोक व्यवस्था संबंधित मामलों के संदर्भ
में विचार विमर्श करना (सैकिंग विनियम
अधिनियम 28/9)

6/15

संसद ही देश की ड्रा लक्ष्य
ड्रा तप काती है इसलिए सरकार लक्ष्य
विपक्ष द्वारा संश्लेष लाखते हुए संसद
की उत्पादकता को बहाना चाही।

12.

श्रीलंका और नेपाल के गणमान्य व्यक्तियों की हालिया भारत यात्रा आपसी संदेह के बावजूद स्थायी संबंध को उजागर करती है। इसके आलोक में आपसी विश्वास तथा साझेदारी में क्षेत्रीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

The recent visit by dignitaries of Sri Lanka and Nepal to India highlights the sustained engagement despite mutual suspicion. In light of this, analyze the role of regional cooperation in mutual trust and partnership. (250 words) 15

श्रीलंका एवं नेपाल भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनके राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की यात्रा की है जिससे दोनों के बीच संबंधों को नयी दिशा मिलेगी।

हालिया यात्रा

दोनों देशों के बीच संबंध मधुर हैं।

→ क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है।

→ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देना है। भारत ने श्रीलंका के विपक्ष में UN में कई वोटों में अड़पावपी इंस की

→ मैक्सिमम पॉजिटीव के क्षेत्रीय देवा है।

→ इन देशों के बीच विवाद के कि-डू के कारण

द्वितीय सहयोग का विवरण

- उम्मीदवार को इस
हॉल में नहीं लिखना
पड़िये।
(Candidate must not
write on this margin)
- * बिहार में आने वाली वाद को
निपट्रित प्रबंधित करने के लिये नेपाल
की सहयोग की जरूरत है।
 - * तामिलनाडु की दुविधा को करने एवं
कच्चाडीबु द्वीप विवाद को लक्ष्य प्राप्त
के लिये नेपाल की सहायता जरूरत है।
 - * द्वितीय कनेक्टिविटी बढाता है।
(कुलाडान मल्ली मॉडल परियोजना,
BCIM.)
 - * उत्तरी राज्यों में बिजली की समस्या
के लिये नेपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का है।
 - * द्वितीय महालागर में चीन के मतदान के
लिये श्रीलंका जरूरत है (श्रीलंका का हवनवेला
वडरंगाट्ट 99 वकी की लीज पर चीन ने लिया)
 - * आंतरिक सुरक्षा एवं शांति के लिये
दोनों के सहयोग की जरूरत है।

पाकेल्यान से अर्बुद शतापी नेपाल से सहो आते है ।

भागे की राह

- द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना चाहिए ।
- वैश्विक मंचों पर लक्ष्य करना
- एक-दूसरे की समृद्धता एवं आयुष्मत्ता को बनाये रखने
- सार्व, विश्वतक संघर्ष / संगठन माध्यम से सहयोग बढ़ाना ।
- कौशल विकास करना (मौलिक शिक्षण द्वारा)

श्रीलंका एवं नेपाल दोनों
 ही भारत की नेबरहुड पालिसी के लिपे
 आवरपु जै है अतः दोनों डे मध्य सहयोग
 एवं विकास की पर्याप्त सहायता है

5
 /
 15

उम्मीदवार को इस
 हाशिये में नहीं लिखना
 चाहिये।
 (Candidate must not
 write on this margin)

13.

सीमाओं के बावजूद, लोक लेखा समिति (PAC) हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिये एक अमूल्य परिसंपत्ति बन गई है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite limitations, the Public Accounts Committee (PAC) has become an invaluable asset to our parliamentary democracy. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को
हाशिये में नहीं
चाहिये।

(Candidate n
write on this

संसद के कार्य संचालन को कुशलता पूर्वक
चलाने हेतु सांविधान के अनुच्छेद 105 एवं 118
में विभिन्न संसदीय समितियों का जिक्र
किया गया है।

लोक लेखा समिति का
कार्यकाल 1 वर्ष होता है यह CAG की रिपोर्टों
की जांच करता है उस समिति का अध्यक्ष
विपक्षी साध्य होता है इनमें 22 के सदस्य
होते हैं इसी प्रकार भारत शासन Act
1919 में उक्त है।

सीमाएं

- अनुपरीक्षण की शक्ति कार्य करती है।
- केवल खर्चों की जांच करती है (सिकारिस)
बाध्यकारी नहीं होती।
- खर्च हो जाने के बाद जांच होती है।
- 1 वर्ष का कार्यकाल होता है जो कि कम है।
- पर्याप्त शक्ति नहीं है।

- सदस्यों की लक्ष्य कट है इसे 22 से बढ़ाकर 30 करना चाहिए
- सदस्यों की अनुपायति रहती है

महत्व

- ICAC की रिपोर्ट की जांच कर CA 4 की प्रसंगिकता को बताती है
- धन के अधिक व्यय से संबंधित जांच करती है
- खर्चों में गिरवपत्त का प्रभाव बताती है
- सरकार को अधिक जवाबदेह बताती है
- सुजनता के मूल निर्माण को प्रभावित करती है
- अध्यक्ष की विपदा का होना इसकी प्रसंगिकता को बताती है
- सिफारिशों को सार्वजनिक को लौपती है जैसे-तैसे पत्र पर रखा जाता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

ज्ञाने की राह

- सदस्यों की संख्या बढ़ायी जाये (30)
- वैठकों की संख्या नियत की जाये
- सदस्यों की उपाधिकार निर्धारित की जाये
- जनता की कार्यवाही भी बढ़ायी जाये
- छोड़ लब्धा में।
- सिक्तियों की जनता को भी उपलब्ध कराया जाये।

अतः लोक से लेना तापित

अतः परीक्षण से बात की 100 वर्ष के

कार्यकाल में अपने महत्व को बढ़ाये

इसे ही उपर्युक्त युक्तियों का समाधान

कर सभी उद्योग को बढ़ाना चाहिए।

अच्छा
प्रयोग
है

14.

अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के लिये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग स्वतंत्र तथा स्वायत्त रहें। समसामयिक मुद्दों पर विचार करते हुए इस पर चर्चा कीजिये।
 (250 शब्द) 15

For ensuring social justice for minorities and women, it is necessary that the National Commission for Minorities and National Commission for Women remain independent and autonomous. Discuss it considering contemporary issues.
 (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
 (Candidate must not write on this margin)

अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु एवं महिलाओं को सशक्त करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने हेतु दोनों आयोगों की स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता अपरिहार्य है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

- अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा
- अल्पसंख्यकों के अध्यापन की सिकाहिरा कावा
- उनके विकास हेतु पर्याप्त अचलत स्वायत्ता एवं सइकाह को सिकाहिरा कावा
- निविधतत उमें एकतय डी कावता को बवाये रखने हेतु अल्पसंख्यकों की संरक्षति

↳ लक्ष्मी एवं सावित्री इयत-धो को पालन के लिये

राष्ट्रीय महिला आयोग

↳ सिविल कोर्ट की शक्ति का

- महिला सरावतिकरण को बढ़ावा देना
- महिलाओं के विकास एवं उत्थान हेतु सिफारिश करना
- पॉन हिला जैसे वैधों की जांच करना
- जेल में बंद महिला कैदियों के आवेषकारों की रक्षा करना
- महिला हैल्पलाइन नम्बर 1091 को चलाना।

समानाधिकार कूट

- महिलाओं के खिलाफ पॉन हिला मामले बढ़ रहे हैं (2011-2021 तक 87% बढ़ि - NCAB)
- माणीपुर हिला में भैरपी समुदाय के खेद हिला
- अल्पसंख्यकों में बढ़ता ग्रुप
- UCC के माध्यमों से राष्ट्रीय स्वीकरण हेतु समान कारा कले की सिफारिश

उम्मीदवार :
 इच्छित में :
 चर्चिते।
 (Candida
 write on

→ सरकारी कठपुतली, वित्तीय निम्नलिखित गाँव

→ देश में बहने लाम्पहापिक इंगी (मुजफ्फर
हिलों, बंगाल हिलों आदि)

→ पाकिस्तान द्वारा भारतीय मुस्लिमों को
असमाना कलहना अमाना

अल्पसंख्यक एवं

माहिवा हानो की सुरक्षित लक्ष्य हैं समावेकी

चड़डुंभी विकास की दिशा में हानो की

सामिलिय करण मानियार्थे हैं अतः

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एवं माहिवा आपारा

को स्वतंत्र एवं स्वायत्त होना चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

सामान्य
वि-ड
लिखने के
बजाय
डोल वि-ड
लिखें।

5/15

15.

कई बाह्य ताकतों ने मध्य-पूर्व में अपना दबदबा कायम रखा है, जो भारत के लिये महत्व रखता है। इस संदर्भ में, मिस्र के साथ भारत के सामरिक संबंधों को मजबूत करने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

Several outside powers have entrenched themselves in the middle east, which is a zone of interest to India. In this context, discuss the implications of India's strengthening of its strategic ties with Egypt.

(250 words) 15

मध्य पूर्व क्षेत्र भारत के वित्तीय पटल के अन्तर्गत आता है जिसके साथ भारत के प्राचीन काल से ही, रेडियु नार्थ माध्यम से संबंध मौजूद है हाल ही में मध्य पूर्व देशों में कतल वपी समूहों ने गठ जमा लिया है

मध्य पूर्व में अनेक हितधारक कौन-2 हैं?

भारत के लिये मध्य पूर्व का महत्व

- भारत की ऊर्जा सुरक्षा हेतु चेहरा विकल्प है (कजाकेलाय के साथ परमाणु समझौता)
- यूरोप अब भारत की पड़ोसै स्ट्रैटेजिक कला है
- भारत निर्माण हेतु नये अवसर में एवं निवेश के उपाय अवसर है
- सैन्य पहुँच स्ट्रैटेजिक कारण हेतु (तणाकाल)

→ पाकिस्तान में आतम के सैन्य अड्डा
स्थापित दिया है।

→ आसगाबा सन्धियाँ 2008 के मध्यय से
मध्य पूर्व के लिए विशेष नीति
संचालित करता है।

इसी दिरा में आतम
सिख डी के साथ संबंधों को
समझून कर मध्य पूर्व वाले लाग बने
है समानरत है।

सिख का महत्व

- * मध्य पूर्व के लाग की अपा लडाखा
की शुद्धि निग सकता है।
- * सिख के साथ संबंध पाकिस्तान के
संयुक्त के लिए जारी है।
- * अपने निषेध को बहने तथा अफ्रीका
तथा यूरोप तक पहुंच बहने है।
- * सिख के साथ शुद्धि समाजिक तैरों

हार्न काँक अफ्रीका के कलरपंथी एवं
जलसंयु लक्ष्यों का सामना करावैले

* पारिचय द्वारा द्वारा नीचे का पदार्थ को
की बहावा मिलता है।

कल: मध्य पूर्व में उपजे

कलरपंथी सभ्यता, आलकवा से निपटने के

लिए आल-मध्य पूर्वी देशों से संबंध

स्थापित कर पाए करते हवे, प्राक्किहों है

साथ ही मिलने के साथ संबंधों को

बहाकर अपनी लक्ष्या एवं पाकिस्तानको

संतुलन का रहा है।

↳ सतही उत्तर है, मौसम उत्तर की दिशा में।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

4.5
15

16.

भारत-अमेरिका संबंध सहयोग और साझेदारी के एक नवीन युग में प्रवेश कर गए हैं। उपर्युक्त कथन के आलोक में आर्थिक, सामरिक और प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण से भारत-अमेरिका संबंधों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

The India-US relationship has entered a new era of collaboration and convergence. In light of the above statement, analyze Indo-US relations from economic, strategic and technological perspectives. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस दृष्टिकोण में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

2005 में भारत अमेरिका द्वरगाण्ड सहयोग के साथ ले ही दोनो के संबंध निरंतर प्रगति पर है साथ ही वर्तमान में चीन की बढ़ती शक्ति ने भारत-USA को और करीब ला दिया है।

प्रश्न को प्रथम भाग लिखें।
संबंध नवीन युग में बढ़े P.

आर्थिक दृष्टि

- USA भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साथी है।
- व्यापार आधेराप है।
- भारत की द्वारा सबसे बड़ा FDI USA से आता है।
- भारतीय प्रवासी के लिए बेहत गत है।
(गूगल रहित - डूंगर विचार)

सामाजिक दृष्टि

उम्मीदवार को इस
दृष्टि में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

→ द्वि. प्रशांत पहल को बहाते डा. वार्ड
का संगठन।

→ सशरी लक्ष्या हेतु LEMOA संगठन।

BECA,
COMESA

→ ~~अपना~~ भारत को विक्रम आर्यन
हापिया उपलब्ध कराता है।

I2U2
2+2
वार्ड

→ भारत की आंतरिक्ष लक्ष्या एवं अजयता
का समर्थन करता है। (चीनी आकाश
पर चीन की क्रिया करेगा)

→ भारत को अपना साथिड आगीडा निरूपित
किया।

प्रौद्योगिकीय आगीडा

→ NASA + ISRO जेडर वेचर निसा उपग्रह
का संक्षण

ICET
संक्षण

→ भारत - USA AI पहल

→ सुचा लंचा प्रौद्योगिकी हेतु समर्थन
(प्रौद्योगिकी संस्था)

उम्मीदवार का इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

→ भारत की सार्वभूमिक सुरक्षा के सहित 50
सार्वभूमिक सुरक्षा सहायता देना

→ रविवर रूपी सौधोगिकी में भागीदारी
बनाना

भारत-USA संबंध वर्तमान

में नयी अचर्या पाई है जिससे भारत
की द्विप महासागर में मजबूत स्थिति
उत्थारित होती है लाप ही दौरो
के मध्य संबंधों को भारत के

5.5
15

आर्थिक सामर्थ्य एवं सौधोगिकी लाभ
उत्थारित होते हैं।

17.

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्वास्थ्य देखभाल वित्तपोषण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

What steps has the government taken to achieve Universal Health Coverage? Discuss the significance of healthcare financing in achieving this target. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

स्वास्थ्य को सार्वभौमिक कवरेज हेतु भारत ने 2018 में आयुक्तमान भारत पहल की शुरुआत की जहाँ जिलों द्वारा 90% जनसंख्या के सम्मिलित होने के साथ ही यह विषय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य कवरेज परिभाषना है।

कदम

- आयुक्तमान तहत जन आरोग्य योजना
- स्वास्थ्य में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना
- ग्राम में लोगों की संख्या बढ़ाई है जसे ग्राम निर्माण की संयुक्ति PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- व्यं अभियान योजना - बूती हेतु
- संबागत तलक के लिए - जननी शिखा

योजना

→ ई-साजिवनी पद्धत की बहुआयु उम्र

स्वास्थ्य डेजनाल विनायोजन अर्थ

- ⊗ गरीबों तक स्वास्थ्य की कवरेज पहुंच होती है।
- ⊗ जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य तक पहुंच
- ⊗ वांचित SC/ST, OBC, महिला, LGBTQ आदि तक पहुंच सुनिश्चित
- ⊗ गरीबों का आर्थिक भार कम करना
- ⊗ समावेशी विकास के माध्यम से स्वास्थ्य की बढ़ावा देना।

→ केवल 1.5% GPP का 1.5% खर्च होता है स्वास्थ्य में

आगे की राह

- वैकल्पिक विकल्प बढ़ते-घाटे में जैसे स्वास्थ्य बीमा कवरेज (4-1% है अभी)
- योजनाओं का प्राथमिकतापूर्ण रिफोकस
- पंचायत समितियों को शामिल करना
- पर्याप्त जागरूकता फैलाना (ग्रामीण महिला)

में 38-1 जननी लक्ष्मी योजना लागू है

→ माहिलाओं पर विशेष धना (58-1. महिला पनिधीया ले ग्रहण है

→ बूढ़, बच्चों, दिव्यांगों उपाय तब पड़ने की वकाना।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार

स्वास्थ्य का अधिकार की अनु-21 के तहत

मूल अधिकार है अतः स्वास्थ्य की सार्वजनिक

जवाब हेतु सरकारी योजनाओं का निष्पक्ष

तब जमीनी तब पर हिमा-वपन होना चाहिए

5/15

18.

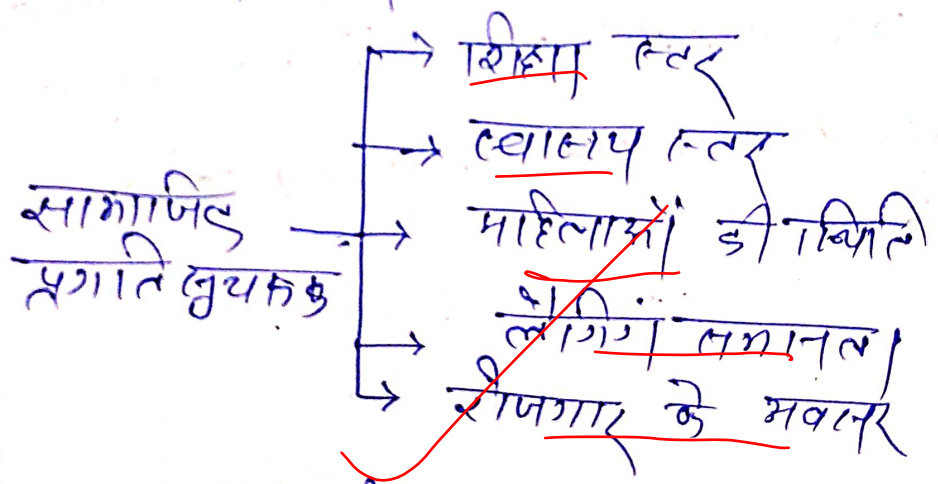
राज्यों और जिलों के लिये सामाजिक प्रगति सूचकांक क्या है? भारत के लिये उप-राष्ट्रीय सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI) जारी करने का क्या महत्त्व है? (250 शब्द) 15

What is the social progress index for states and districts? What is the significance of releasing the sub-national Social Progress Index (SPI) for India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

राज्यों एवं जिलों के लिये सामाजिक प्रगति सूचकांक (SPI) जारी करने का क्या महत्त्व है? किया जा रहा है जिलों की सरकारी योजना बनाने एवं क्रियान्वयन करने में आसानी हो।

प्रश्न का मैं SPI को बता रहा हूँ



स्थायी स्तर पर प्रगति को मापने एवं योजनाओं की बेहतर रूप से तन्वोलिका करने हेतु बलडी विशेष उपयोगिता होती है

उप-राष्ट्रीय प्रगति (सामाजिक) सूचकांक

- आंकड़ों तक पहुँच होती है
- आंकड़ों से बेहतर योजना निर्माण होता है
- कम प्रगति वाले इलाकों में सरकार द्वारा विशेष जोर दिया जाता है
- महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है

→ लैंगिक समानता हेतु सरकार एक पहल है
(नेशनल रिपोर्ट 135/154)

→ स्थानीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक
प्रगति को ही मापता है

→ सामाजिक विकास
→ आर्थिक विकास
↓
सामाजिक विकास

चुनौतियाँ

- प्रौद्योगिकी का सीमित प्रयोग
- डेटा के रखरखाव के आवस्यताओं की
समस्या
- प्रगति मापन की अपवर्ति शक्ति कैसे?
- पर्याप्त वत्रे उपलब्ध न होना दे फिर क्या है?

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

आगे की राह

- डिजिटल रखरखाव का माध्यमिकरण
- प्रौद्योगिकी माध्यम से जबआगीदारी की
बहाना
- डिजिटल एकत्रीकरण से यथार्थ महत्व डेना
समंवलन डिजिटल एकत्रीकरण
- महिला एवं वंचितों पर विशेष ध्यान
स्थानीय तहसील पर सामाजिक
प्रगति को मापने एवं उसे बढ़ावा
देने की दिशा में बहुरंग रूप से कतः
उपर्युक्त न्यूनताओं का समाधान कर
प्रगति सूचकांक की उन्नति को बढ़ावा
जाना चाहिए।

4.5
15

→ आवधारण कर लगाए जाएँ।

19.

भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में धारा 124A के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसके प्रभाव का आकलन कीजिये तथा राष्ट्रीय सुरक्षा व मूल अधिकारों को संतुलित करने के लिये सुधारों का प्रस्ताव दीजिये। (250 शब्द) 15

Analyze the significance of section 124A in retaining the unity and integrity of India. Assess its impact on freedom of speech and expression and propose reforms for balancing national security and fundamental rights. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस शीट पर नहीं लिखना चाहिए।
(Candidate must not write on this margin)

ब्रिटिशों द्वारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन
को कुचलने के उद्देश्य से 1894 में धारा
124A लाई गयी थी। जिसमें विभिन्न
राजनेताओं को लजा दी गई थी। स्वतंत्रता के
बाद भी यह राजतंत्र का नुस्तान है।

महत्त्व

- देश की एकता एवं अखंडता हेतु पर्याप्त
मजदूरी है।
- असमाजिक तत्वों, आतंकवादी तत्वों के
निपटने में सहायक
- लोक व्यवस्था एवं कानून हेतु आवश्यक
- देश शांति एवं विकास हेतु अव्यक्त

वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रभाव

- व्यक्ति की अस-19(1) के अधिकार को

केवल नाम लिखें वनाम
मिहल राजा काप
उम्मीदवार को इस
इतिहास को नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

हीन लीपा पाला है।

→ हीन स्पीच की दिशा में यह लकारात्मक
मस्य है।

→ अनिवार्य स्वतंत्रता बाधित होती है।

→ इस का माहौल बनता है।

→ स्वल्प लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है।

सुधार

→ विभिन्न देशों में ऐसे कानून नहीं हैं
(USA, ब्रिटेन में भी अब नहीं हैं)

→ मूल अधिकारों को इसके तहत बनाये
रखा जा सकता है।

→ राष्ट्रीय सुरक्षा को लायायेक महत्व
देंना चाहिए।

→ दुरुपयोग को कम करना चाहिए (NCRB
जैसा नक्ष द्रोष सिद्धि इस मात्र प. 1. है)

→ जनता को की बात मस्य में जागत्य
दिया जाये।

5 कानून
में
1-48881
लाना

→ सापेक्ष क्यापी जाये वसके हतने पर
विचार किया जाये पहले ही पडैय

कानून मौजूद है (UAPA, AfSPA, NSA etc)

→ कानून बनाने समय जनता की राय
पाननी चाहिए ताकि स्वल्प लोकतंत्र
का निर्माण हो सके ।

द्वारा 12PA के
दुरुपयोग के आखिर मानके रहे उन्हें

कह सकते हुए द्वारा 12PA के हतने
पर विचार किया जाना चाहिए तब सापेक्ष
का गठन किया जाना चाहिए तभी
स्वल्प लोकतंत्र का निर्माण हो सकेगा ।

उम्मीदवार को
उत्तरों में नई
लिखनी है।
(Candidate
write on th

5/5

20.

फेक न्यूज के प्रसार को नियंत्रित करने में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है? फेक न्यूज के प्रसार को रोकने में सिविल सेवकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

What is the role of civil servants in regulating the spread of fake news? Discuss the challenges faced by Civil servants in curbing the spread of fake news. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

NCRB डेटा से अनुसार फेक न्यूज मामले 2021 में 457 दर्ज किये गये थे जो 2022 में बढ़कर लगभग 1600 हो गये हैं। कक्षाप ही फेक न्यूज संबंधी 15 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक दिया गया है।

आंकों की शुद्धि करें

प्रसार नियंत्रित करने में सिविल सेवकों की भूमिका

- CS (सिविल सेवक) को लोक व्यवस्था को बनाये रखने हेतु संरक्षित होता है।
- अत्याधिक प्रसार में कानून के माध्यम से डाल दिया जा सकता है।
- CS अपनी कार्य शैली में पारदर्शिता लाते हुए फेक न्यूज हेतु विशेष नियम बना सकता है।
- साम्प्रदायिक हलों जैसी फेक न्यूज के

मापलें में इतरंगत कट बाववा लकता है
 → जनता में विक्रिय सिमिता के माध्यम
 से जागतकता कौला लकता है

उम्मीदवार को इस
 मार्ग में नहीं लिखना
 चाहिए।
 (Candidate must not
 write on this margin)

चुनौतियाँ

- पर्याप्त शौधांगिकी उपलब्ध होना जिससे नियंत्रित करने में समय लगता है
- जनता में जागतकता, शिक्षा की कमी
- डिजिटल डिवाइस (WB → SP → कलेमाल नहीं करते)
- तीन वर्ड की कठिनाई का शभाव
- कर्मचारियों को शौधांगिकी की व्यापक समझ न होना
- कुशल IT इंजीनियर की कमी (5 लाख कुशल इंजी की कमी है)
- जनता द्वारा इतरंगत काल्डाउन का विकल्प दिया जाना
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ विरोधाभास

→ राजनीतिक 4 बात
 → सीपके के
 → काल्डाउन

आगे की राह

- जनता की शिक्षित दिया जाना चाहिए।
- पथरित जागतिकता फैलाई जाये।
- सिविल सेवकों को भी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण दिया जाये।
- बड़े कुशल इंजीनियर, डी गरीबों की जाये।
- गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ावा दिया जाये।
- प्रौद्योगिकी क्षेत्र में R&D को बढ़ावा दिया जाये।

इस इलेक्ट्रॉन के बड़े उपयोग के साथ ही कुछ न्यून जैसी समस्या को भी बढ़ावा मिला है अतः रात दिशा में कई काम बनाने चाहिए।
वर्तमान में आपा IT नियम 2015 इस दिशा में सराहनीय काम है।